



पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

Ministry of Panchayati Raj
Government of India



Best Practices of Awardee Gram Panchayats and Institutions

**Special Category Awards
(National Panchayat Awards 2025)**

पुरस्कृत ग्राम पंचायतों और संस्थाओं की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली

**विशेष श्रेणी पुरस्कार
(राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025)**



सशक्त पंचायत सतत विकास

Preface

India's unwavering commitment to the United Nations' 2030 Agenda for Sustainable Development reflects a deep and enduring belief in the strength of inclusive and grassroots governance. With over 2.5 lakh Gram Panchayats and more than 32 lakh elected representatives, the Panchayati Raj system serves as the foundation of democratic decentralisation, playing a transformative role in aligning local aspirations with national development objectives.

National Panchayat Awards, conferred annually by Ministry of Panchayati Raj on 24th April celebrated as National Panchayati Raj Day acts as a key motivator for Panchayats. This day marks the enactment of the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, which came into effect in 1993, granting Panchayats constitutional status as institutions of local self-governance. These awards not only recognise outstanding performance but also create a platform for knowledge exchange and peer learning among Panchayats and States/UTs.

The 2025 year of the *Special Category Awards* marks a significant advancement in this journey. This year, a new category **Atma Nirbhar Panchayat Special Award (ANPSA)** has been introduced, placing a strategic emphasis on fiscal self-reliance and the capacity of Panchayats to generate and manage their own revenues in support of *Atmanirbharta*. This addition reflects the Ministry's evolving focus on financial autonomy as a cornerstone of effective and sustainable local governance.

Similarly, two existing categories namely, *Gram Urja Swaraj Vishesh Panchayat Puraskar* and *Carbon Neutral Vishesh Panchayat Puraskar* have been consolidated to form the **Climate Action Special Panchayat Award (CASPA)**. This award is for those Panchayats which have undertaken exemplary efforts in adopting renewable energy, promoting environmental sustainability, and advancing carbon neutrality at the grassroots level. Further, the **Panchayat Kshamta Nirmaan Sarvottam Sansthan Puraskar (PKNSSP)** continues to recognise institutions that have provided outstanding institutional support to Panchayats in achieving the objectives of LSDGs. These organisations play a pivotal role in strengthening the ecosystem of rural governance through training, research, and capacity building.

Under the Special Category Awards 2025 (Appraisal Year 2023–24), a total of **6 Gram Panchayats and 3 Institutions** across **8 States** namely Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, and Telangana were conferred with *Special Category Awards* under the National Panchayat Awards 2025. Notably, **three of the six awardee Gram Panchayats** are led by **women Sarpanches** from Bihar (*Mothipur Gram Panchayat*), Maharashtra (*Dawwa S Gram Panchayat*), and Odisha (*Hatbadra Gram Panchayat*), underscoring the growing leadership of women in local governance.



The Special Category Awards 2025 were conferred to 6 Gram Panchayats and 3 Institutions by Hon'ble Prime Minister of India during National Panchayati Raj Day-2025 held on 24.04.2025 at Lohna Uttar Gram Panchayat, District Madhubani, Bihar. The event was also graced by Hon'ble Chief Minister of Bihar and other Central Ministers and Ministers of G/o Bihar.

This eBook presents a curated record of the Special Category Awards 2025, capturing the achievements of award-winning Panchayats and institutions. It stands as a testament to the potential of decentralised governance in driving India's development narrative. By showcasing replicable models of success, this publication aspires to inform, inspire, and catalyse further innovation among Panchayats and stakeholders committed to building a sustainable and self-reliant rural India.

 <https://www.youtube.com/watch?v=SkF0v6FaX3U>

(Consolidated Video film covering the aspects including on Special Category Awards under National Panchayat Awards 2025: Refer duration 0.53 minutes to 1.47 minutes specifically for National Panchayat Awards)



प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता समावेशी और जमीनी स्तर के शासन की ताकत में गहरा और स्थायी विश्वास को दर्शाती है। 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 32 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ, पंचायती राज प्रणाली लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव के रूप में कार्य करती है, जो स्थानीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय विकास उद्देश्यों के साथ जोड़ने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाती है।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पंचायतों के लिए एक प्रमुख प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। यह दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अधिनियमन का प्रतीक है, जो 1993 में लागू हुआ, जिसने पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया। ये पुरस्कार न केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं, बल्कि पंचायतों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान करने और सहकर्मियों से सीखने के लिए एक मंच भी प्रदान करते हैं।

विशेष श्रेणी पुरस्कार वर्ष 2025 इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। इस वर्ष, एक नई श्रेणी **आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार** शुरू की गई है, जिसमें वित्तीय आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता के समर्थन में पंचायतों की अपनी खुद की आय सृजित करने और प्रबंधित करने की क्षमता पर रणनीतिक रूप से जोर दिया गया है। यह वृद्धि प्रभावी और स्थायी स्थानीय शासन की आधारशिला के रूप में वित्तीय स्वायत्तता पर मंत्रालय के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

उसी प्रकार, दो मौजूदा श्रेणियों, **ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार** और **कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार** को **क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार** बनाने के लिए समेकित किया गया है। यह पुरस्कार उन पंचायतों के लिए है जिन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर कार्बन न्यूट्रलिटी को आगे बढ़ाने में अनुकरणीय प्रयास किए हैं। इसके अलावा, **पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार** उन संस्थाओं को मान्यता देना जारी रखता है जिन्होंने एलएसडीजी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पंचायतों को उत्कृष्ट संस्थागत सहायता प्रदान की है। ये संगठन प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीण शासन के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विशेष श्रेणी पुरस्कार 2025 (मूल्यांकन वर्ष 2023-24) के अंतर्गत, **8 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना की कुल 6 ग्राम पंचायतों और 3 संस्थाओं** को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत विशेष श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि **छः पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों में से तीन** नामतः बिहार (मोतीपुर ग्राम पंचायत), महाराष्ट्र (दव्वा एस ग्राम पंचायत) और ओडिशा (हटबद्रा ग्राम पंचायत) का नेतृत्व **महिला सरपंचों** द्वारा किया जाता है, जो स्थानीय शासन में महिलाओं के बढ़ते नेतृत्व को रेखांकित करता है।



दिनांक 24.04.2025 को बिहार के मधुबनी जिले के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2025 के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 6 ग्राम पंचायतों और 3 संस्थाओं को विशेष श्रेणी पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री भी मौजूद थे।

यह ई-बुक विशेष श्रेणी पुरस्कार 2025 का एक संकलित रिकॉर्ड प्रस्तुत करती है, जिसमें पुरस्कार विजेता पंचायतों और संस्थानों की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। यह भारत के विकास की गाथा को आगे बढ़ाने में विकेंद्रीकृत शासन की क्षमता का एक प्रमाण है। सफलता के अनुकरणीय मॉडल का प्रदर्शन करके, यह प्रकाशन एक स्थायी और आत्मनिर्भर

ग्रामीण भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध पंचायतों और हितधारकों के बीच आगे के नवाचार को सूचित, प्रेरित और उत्प्रेरित करने की आकांक्षा करता है।

<https://www.youtube.com/watch?v=SkF0v6FaX3U>

(राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विशेष श्रेणी पुरस्कारों सहित विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाली समेकित वीडियो फिल्म: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए विशेष रूप से 0.53 मिनट से 1.47 मिनट की अवधि देखें)



Special Category Awards
(National Panchayat Award 2025)





Best Practices of awardee Gram Panchayats and Institutions










Climate Action Special Panchayat Award (CASPA)-2025

CASPA has been instituted during the year 2025 by clubbing earlier 2 awards of Gram Urja Swaraj Vishesh Panchayat Puraskar and Carbon Neutral Vishesh Panchayat Puraskar. This award is for Gram Panchayats (GPs) for their performance regarding adoption and usage of renewable energy and efforts towards achieving carbon neutrality towards mitigation of climate change.












A Panchayat taking measures towards climate action is one that:

-  Achieves net zero carbon emissions and significantly reduces carbon dioxide emissions
-  Promotes 100% use of renewable energy sources such as wind, solar, and hydel power
-  Undertakes offsetting and mitigation measures to reduce the emission of Greenhouse Gases
-  Ensures self-sufficiency in energy through sustainable and eco-friendly practices

Local Goals and Targets:

-  Achieve Open Defecation Free status
-  100% waste management and effective solid and liquid waste disposal
-  Zero use of plastic
-  100% transition to renewable energy sources for household, transportation, and industrial needs
-  Conservation and expansion of forests and biodiversity
-  Reduction of carbon emissions from all sectors — households, transportation, and industry
-  Soil and water conservation through traditional and innovative practices

Role of Gram Panchayats:

-  Conduct baseline surveys to assess total carbon emissions and energy requirements
-  Ban the use of plastic within the Panchayat area
-  Implement effective management systems for solid and liquid waste
-  Generate awareness and mobilize the community, authorities, organizations, and all stakeholders towards climate goals
-  Promote the use of renewable energy sources for electricity generation, water heating and cooling, and transportation
-  Encourage the use of biogas as a household and industrial fuel
-  Promote organic agriculture and reduce dependency on chemical fertilizers
-  Practice traditional methods of carbon offsetting as potential sources of community revenue
-  Undertake extensive tree plantation drives and promote forest conservation
-  Implement innovative financial models such as tree banking and tree mortgaging
-  Ensure convergence and optimal utilization of Gram Panchayat Development Plan (GPDP) funds along with other government schemes and programs for climate action

विशेष श्रेणी पुरस्कार
(राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025)

पुरस्कृत ग्राम पंचायतों और संस्थाओं की सर्वोत्तम कार्यपद्धति

क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार-2025



क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2025 के दौरान ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार और कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार के दो पुरस्कारों को मिलाकर की गई है। यह पुरस्कार ग्राम पंचायतों को नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और उपयोग करने तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के प्रयासों के लिए दिया जाता है।

क्लाइमेट एक्शन के लिए कदम उठाने वाली पंचायत वह है जो:

- 🌱 नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाती है
- 🌱 पवन, सौर और जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के 100% उपयोग को बढ़ावा देती है
- 🌱 ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ऑफसेटिंग और शमन उपाय करती है
- 🌱 स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल कार्यों के माध्यम से ऊर्जा में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करती है

स्थानीय लक्ष्य एवं उद्देश्य:

- 🌱 खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा प्राप्त करना
- 🌱 100% अपशिष्ट प्रबंधन और प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान
- 🌱 प्लास्टिक का शून्य उपयोग
- 🌱 घरेलू, परिवहन और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर 100% संक्रमण
- 🌱 वनों और जैव विविधता का संरक्षण और विस्तार
- 🌱 सभी क्षेत्रों - घरेलू, परिवहन और उद्योग से कार्बन उत्सर्जन में कमी
- 🌱 पारंपरिक और नवीन कार्यों के माध्यम से मृदा और जल संरक्षण

ग्राम पंचायतों की भूमिका:

- 🌱 कुल कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित करना
- 🌱 पंचायत क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना
- 🌱 ठोस और तरल अपशिष्ट के लिए प्रभावी प्रबंधन प्रणाली लागू करना
- 🌱 जलवायु लक्ष्यों के प्रति समुदाय, अधिकारियों, संगठनों और सभी हितधारकों को जागरूक करना और उन्हें संगठित करना
- 🌱 बिजली उत्पादन, पानी गर्म करने और ठंडा करने तथा परिवहन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना
- 🌱 घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में बायोगैस के उपयोग को प्रोत्साहित करना
- 🌱 जैविक कृषि को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना
- 🌱 समुदाय के राजस्व के संभावित स्रोतों के रूप में कार्बन ऑफसेटिंग के पारंपरिक तरीकों का अभ्यास करना
- 🌱 व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाना और वन संरक्षण को बढ़ावा देना
- 🌱 ट्री बैंकिंग और ट्री मोर्टगेजिंग (ट्री गिरवी) जैसे नवीन वित्तीय मॉडल लागू करना
- 🌱 क्लाइमेट एक्शन के लिए अन्य सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ-साथ ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) निधियों का अभिसरण और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना

Best Practices of awardee Gram Panchayats: Climate Action Special Panchayat Award (CASPA)-2025

Rank 1: Dawwa S Gram Panchayat (Block Sadak Arjuni, District Gondia), Maharashtra

Profile of Gram Panchayat

- Local Government Directory (LGD) Code: 175545
- Total household: 796
- Population: 3418

Key Achievements

- Afforestation Drive: Planted 116,643+ indigenous trees, 5,000 bamboo, 500 moringa, and vetiver—each household contributed 15–20 trees
- State Recognition: Secured 3rd rank in Maharashtra's *Majhi Vasundhara 4.0* program for environmental excellence
- Solar Infrastructure: Installed solar PV systems in schools, anganwadis, and public buildings
- Inclusive Access: Distributed 80 solar kits to differently-abled residents for energy independence
- LED Coverage: Achieved 100% LED adoption, reducing energy use and emissions
- Carbon & Water Gains: Increased tree canopy by 10%, improved carbon sequestration, and groundwater recharge
- Plastic-Free: Actively promoted ban on single-use plastics through pledges, awareness drives, and signage

Video on best practices/achievements: <https://youtu.be/ni0TfQtNlMA>



Rank 2: Biradahalli Gram Panchayat (Block Sakaleshpur, District Hassan), Karnataka

Profile of Gram Panchayat

- Local Government Directory (LGD) Code: 218437
- Total household: 950
- Population: 4145

Key Achievements

- Installed rooftop solar for GP office and key public utilities
- Deployed 21 high-mast and 190 mini solar street lights
- Distributed solar lanterns to weaker sections
- Achieved 100% LPG and biogas use in households
- Planted over 1 lakh saplings under Vanamahotsava & MGNREGS
- Promoted solar pumps, solar water heaters, and EV awareness
- Established solid waste management and kitchen gardens
- Conducted 4 inclusive Gram Sabhas promoting climate action

Video on best practices/achievements: <https://youtu.be/2ZillwCtu8Y?si=bccO3sYtKOQ0QRm->



Rank 3: Mothipur Gram Panchayat (Block Rosera, District Samastipur), Bihar

Profile of Gram Panchayat

- Local Government Directory (LGD) Code: 100332
- Total household: 1684
- Population: 10,536

Key Achievements

- Rejuvenated 21 ponds & 2 Amrit Sarovars for rainwater harvesting & fish farming
- Resolved waterlogging over 250 acres using 4 ditches under MGNREGS
- Planted 60,000+ trees; promoted Miyawaki plantations & Nutri Gardens
- Distributed 10 trees for every girl child born
- Ensured piped drinking water under *Har Ghar Nal ka Jal* scheme
- Built 560+ soak pits & a 19,000-ft drainage system
- Established door-to-door waste collection, segregation, and biogas production
- Installed solar street lights, smart classes, biogas in 132 homes, and 32 solar pumps
- Conducted awareness programs on climate change and plastic pollution

Video on best practices/achievements: <https://youtu.be/2UjpHirdUjM?si=A8yiOhSYc9UumVs2>



पुरस्कृत ग्राम पंचायतों की सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों: क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार-2025

रैंक 1: दवा एस ग्राम पंचायत (ब्लॉक सड़क अर्जुनी, जिला गोंदिया), महाराष्ट्र

ग्राम पंचायत का परिचय

- स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 175545
- कुल परिवार: 796
- जनसंख्या: 3418

प्रमुख उपलब्धियाँ

- वनरोपण अभियान: 116,643 से अधिक देशी पेड़, 5,000 बांस, 500 मोरिंगा और वेटिवर लगाए गए - प्रत्येक घर ने 15-20 पेड़ लगाए
- राज्य मान्यता: पर्यावरण उत्कृष्टता के लिए महाराष्ट्र के माझी वसुंधरा 4.0 कार्यक्रम में तीसरा स्थान प्राप्त किया
- सौर अवसंरचना: स्कूलों, आंगनवाड़ियों और सार्वजनिक भवनों में सौर पीवी सिस्टम स्थापित किए गए
- समावेशी पहुँच: ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए दिव्यांग निवासियों को 80 सौर किट वितरित किए गए
- एलईडी कवरेज: 100% एलईडी अपनाने की उपलब्धि हासिल की, जिससे ऊर्जा उपयोग और उत्सर्जन में कमी आई
- कार्बन और जल लाभ: वृक्षों की छतरी में 10% की वृद्धि हुई, कार्बन पृथक्करण में सुधार हुआ और भूजल पुनर्भरण हुआ
- प्लास्टिक-मुक्त: प्रतिज्ञाओं, जागरूकता अभियानों और साइनेज के माध्यम से एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया

सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों/उपलब्धियों पर वीडियो: <https://youtu.be/mi0TfQtNlMA>



रैंक 2: बिरडाहल्ली ग्राम पंचायत (ब्लॉक सकलेशपुर, जिला हासन), कर्नाटक

ग्राम पंचायत का परिचय

- स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 218437
- कुल परिवार: 950
- जनसंख्या: 4145

प्रमुख उपलब्धियाँ

- ग्राम पंचायत कार्यालय और प्रमुख सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए छत पर सौर ऊर्जा स्थापित की गई
- 21 हाई-मास्ट और 190 मिनी सौर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई
- कमजोर वर्गों को सौर लालटेन वितरित की गई
- घरों में 100% एलपीजी और बायोगैस का उपयोग किया गया
- वन महोत्सव और मनरेगा के तहत 1 लाख से अधिक पौधे लगाए गए
- सौर पंप, सौर वॉटर हीटर और ईवी जागरूकता को बढ़ावा दिया गया
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और रसोई उद्यान स्थापित किए गए
- जलवायु कार्यवाई को बढ़ावा देने के लिए 4 समावेशी ग्राम सभाएँ आयोजित की गई

सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों/उपलब्धियों पर वीडियो: <https://youtu.be/2ZillwCtu8Y?si=bcc03sYtKOQ0QRm->



रैंक 3: मोतीपुर ग्राम पंचायत (ब्लॉक रोसेरा, जिला समस्तीपुर), बिहार

ग्राम पंचायत का परिचय

- स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 100332
- कुल परिवार: 1684
- जनसंख्या: 10,536

प्रमुख उपलब्धियाँ

- वर्षा जल संचयन और मछली पालन के लिए 21 तालाबों और 2 अमृत सरोवरों का जीर्णोद्धार किया
- मनरेगा के तहत 4 खाइयों का उपयोग करके 250 एकड़ से अधिक जलभराव को हल किया
- 60,000 से अधिक पेड़ लगाए; मियावाकी वृक्षारोपण और पोषक उद्यानों को बढ़ावा दिया
- जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका के उपलक्ष में 10 पेड़ वितरित किए
- हर घर नल का जल योजना के तहत पाइप से पेयजल सुनिश्चित किया
- 560 से अधिक सॉक पिट्स और 19,000 फीट की जल निकासी प्रणाली बनाई
- घर-घर जाकर कचरा संग्रहण, पृथक्करण और बायोगैस उत्पादन संरचना लगाई गई
- 132 घरों में सोलर स्ट्रीट लाइट, स्मार्ट क्लास, बायोगैस और 32 सोलर पंप लगाए
- जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक प्रदूषण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए

सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों/उपलब्धियों पर वीडियो: <https://youtu.be/2UjpHirdUjM?si=A8yi0hSYc9UumVs2>





Atma Nirbhar Panchayat Special Award (ANPSA)-2025

Atma Nirbhar Panchayat Special Award recognizes Gram Panchayats (GPs) that demonstrate exceptional performance in mobilizing and augmenting their Own Sources of Revenue (OSR). It promotes the spirit of self-reliance at the grassroots by encouraging Panchayats to become financially independent, thus strengthening the foundation of local governance.

An Atma Nirbhar Gram Panchayat is one that:

- 🌸 Achieves a significant increase in local revenue generation without overburdening the community
- 🌸 Utilizes innovative methods to mobilize financial resources
- 🌸 Ensures transparent, accountable management of the revenue
- 🌸 Establishes self-sustaining models to fund development projects and service delivery

Local Goals and Targets:

- 🌸 Achieve fiscal autonomy and reduce dependence on external funding
- 🌸 Maximize the generation of revenue through taxes, fines, fees, and other sources
- 🌸 Strengthen systems for managing and accounting for local finances
- 🌸 Introduce innovative models to increase local income, such as eco-tourism or small-scale enterprises
- 🌸 Enhance transparency and participation in financial decision-making within the Panchayat
- 🌸 Promote the responsible use of resources for sustainable local development

Role of Gram Panchayats:

- 🌸 Conduct regular assessments to identify potential revenue streams within the community
- 🌸 Implement simple and fair taxation systems that benefit both the Panchayat and its residents
- 🌸 Raise awareness about the importance of revenue generation and its impact on local development
- 🌸 Establish partnerships with local businesses, NGOs, and other stakeholders to generate income
- 🌸 Optimize the use of Gram Panchayat assets, such as common lands or infrastructure, for revenue generation
- 🌸 Ensure transparency and accountability in the management of funds through regular audits and public reporting
- 🌸 Foster community participation to strengthen local governance and financial responsibility

आत्म निर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (एएनपीएसए)-2025



आत्म निर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार उन ग्राम पंचायतों (जीपी) को मान्यता देता है जो राजस्व के अपने स्रोतों (ओएसआर) को जुटाने और बढ़ाने में असाधारण प्रदर्शन करते हैं। यह पंचायतों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने के लिए प्रोत्साहित करके जमीनी स्तर पर आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय शासन की नींव मजबूत होती है।

एक आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत वह है जो:

- समुदाय पर अधिक बोझ डाले बिना स्थानीय राजस्व सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करती है
- वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए नवाचार तरीकों का उपयोग करती है
- राजस्व का पारदर्शी, जवाबदेह प्रबंधन सुनिश्चित करती है
- विकास परियोजनाओं और सेवा प्रदायगी को वित्तपोषित करने के लिए आत्मनिर्भर मॉडल स्थापित करती है

स्थानीय लक्ष्य और उद्देश्य :

- राजकोषीय स्वायत्तता प्राप्त करें और बाहरी वित्तपोषण पर निर्भरता कम करना
- करों, जुर्मानों, शुल्कों और अन्य स्रोतों के माध्यम से राजस्व सृजन को बढ़ाना
- स्थानीय वित्त प्रबंधन और लेखा-जोखा के लिए प्रणालियों को मजबूत करना
- स्थानीय आय बढ़ाने के लिए इको-टूरिज्म या लघु-स्तरीय उद्यम जैसे अभिनव मॉडल पेश करना
- पंचायतों में वित्तीय निर्णय लेने में पारदर्शिता लाएं और भागीदारी बढ़ाना
- स्थायी स्थानीय विकास के लिए संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना

ग्राम पंचायतों की भूमिका:

- समुदाय में संभावित राजस्व धाराओं की पहचान करने के लिए नियमित मूल्यांकन करना
- सरल और निष्पक्ष कराधान प्रणाली लागू करें जो पंचायत और उसके निवासियों दोनों को लाभान्वित करना
- राजस्व सृजन के महत्व और स्थानीय विकास पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना
- आय उत्पन्न करने के लिए स्थानीय व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी स्थापित करना
- राजस्व सृजन के लिए ग्राम पंचायत की परिसंपत्तियों, जैसे कि आम भूमि या बुनियादी ढाँचे का उपयोग अनुकूलित करना
- नियमित लेखापरीक्षा और सार्वजनिक रिपोर्टिंग के माध्यम से निधियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना
- स्थानीय शासन और वित्तीय जिम्मेदारी को मजबूत करने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना

Best Practices of awardee Gram Panchayats: Atma Nirbhar Panchayat Special Award (ANPSA)-2025

Rank 1: Mall Gram Panchayat (Block Yacharam, District Rangareddi), Telangana

Profile of Gram Panchayat

- Local Government Directory (LGD) Code: 210571
- Total household: 1581
- Population: 3211

Key Achievements

- Rs.95 lakhs OSR collected during 2023-24 (increase by 45% w.r.t. previous year)
- Rs. 2,954 approx. per capita OSR
- Generated income from special taxes (lighting, drainage) and service fees
- Earned ₹67 Lakhs from the weekly cattle market
- Earned ₹3.75 Lakhs from shopping complexes



Video on best practices/achievements: https://youtu.be/6ORVAna1KOk?si=o_9VwjsWWY6Kbjhs

Rank 2: Hatbadra Gram Panchayat (Block Kusumi, District Mayurbhanj), Odisha

Profile of Gram Panchayat

- Local Government Directory (LGD) Code: 120264
- Total household: 1552
- Population: 6703

Key Achievements

- Rs.94 lakhs OSR collected during 2023-24 (increase by 20% w.r.t. previous year)
- Rs. 1,407 approx. per capita OSR
- Income source include weekly haat/local market tax
- Earned from water tax, safai tax, trade licenses, slaughterhouse auctions, and ad tax
- Non-tax revenue grew by 66.29%, including public property usage and leasing
- ₹18.45 Lakhs allocated for employment generation
- LSDG-aligned spend on water, poverty alleviation, child welfare, healthcare, green projects, and women's development
- Invested in roads, bridges, irrigation, market upgrades, and public amenities
- Strong community trust reflected in voluntary contributions and asset monetization



Video on best practices/achievements: https://youtu.be/3a4eJL_-k98?si=20pChqfn7kPW5vCs

Rank 3: Gollapudi Gram Panchayat (Block Vijayawada Rural, District Krishna), Andhra Pradesh

Profile of Gram Panchayat

- Local Government Directory (LGD) Code: 203825
- Total household: 9460
- Population: 37349

Key Achievements

- Rs.4.11 crore OSR collected during 2023-24 (increase by 40% w.r.t. previous year)
- Rs. 1,130 approx. per capita OSR
- Built 3 water tanks and renovated 5 km of roads using own funds
- Implemented door-to-door waste collection, reducing unmanaged waste by 60%
- Installed 50 solar streetlights, cutting electricity costs
- Achieved 80% self-reliance in operational expenses



Video on best practices/achievements: <https://youtu.be/KfvNvHlFEyQ?si=wPz1pLKT-iGeTHhH>

पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों की सर्वोत्तम पद्धतियाँ: आत्म निर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार-2025

रैंक 1: मॉल ग्राम पंचायत (ब्लॉक याचारम, जिला रंगारेड्डी), तेलंगाना

ग्राम पंचायत का परिचय

स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 210571

कुल परिवार: 1581

जनसंख्या: 3211

प्रमुख उपलब्धियाँ

- वर्ष 2023-24 के दौरान 95 लाख रुपये का ओएसआर (स्वयं स्रोत राजस्व) संग्रह (पिछले वर्ष की तुलना में 45% की वृद्धि)
- लगभग 2,954 रुपये प्रति व्यक्ति ओएसआर
- विशेष करों (प्रकाश, जल निकासी) और सेवा शुल्क से आय अर्जित की
- साप्ताहिक पशु बाजार से 67 लाख रुपये अर्जित किये
- शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से 3.75 लाख रुपये की अर्जित किये



सर्वोत्तम पद्धतियों/ उपलब्धियों पर विडियो: https://youtu.be/6ORVAna1KOK?si=o_9VwjsWWY6Kbjhs



रैंक 2: हटबदरा ग्राम पंचायत (ब्लॉक कुसुमी, जिला मयूरभंज), ओडिशा

ग्राम पंचायत का परिचय

स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 120264

कुल परिवार: 1552

जनसंख्या: 6703

प्रमुख उपलब्धियाँ

- वर्ष 2023-24 के दौरान 94 लाख रुपये का ओएसआर संग्रह (पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि)
- प्रति व्यक्ति ओएसआर लगभग 1,407 रुपये
- आय स्रोत में साप्ताहिक हाट/स्थानीय बाजार कर शामिल है
- जल कर, सफाई कर, व्यापार लाइसेंस, बूचड़खाने की नीलामी और विज्ञापन कर से अर्जित आय
- सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग और पट्टे सहित गैर-कर राजस्व में 66.29% की वृद्धि हुई
- रोजगार सृजन के लिए ₹18.45 लाख आवंटित
- पानी, गरीबी उन्मूलन, बाल कल्याण, स्वास्थ्य सेवा, हरित परियोजनाओं और महिला विकास पर LSDG-संरेखित व्यय
- सड़कों, पुलों, सिंचाई, बाजार उन्नयन और सार्वजनिक सुविधाओं में निवेश किया गया
- स्वैच्छक योगदान और परिसंपत्ति मुद्राकरण में मजबूत सामुदायिक विश्वास परिलक्षित हुआ



सर्वोत्तम पद्धतियों/ उपलब्धियों पर विडियो: https://youtu.be/3a4ell_-k98?si=20pChqfn7kPW5vCs



रैंक 3: गोलापुडी ग्राम पंचायत (ब्लॉक विजयवाड़ा ग्रामीण, जिला कृष्णा), आंध्र प्रदेश

ग्राम पंचायत का परिचय

स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 203825

कुल परिवार: 9460

जनसंख्या: 37349

प्रमुख उपलब्धियाँ

- वर्ष 2023-24 के दौरान 4.11 करोड़ रुपये का ओएसआर संग्रह (पिछले वर्ष की तुलना में 40% की वृद्धि)
- प्रति व्यक्ति ओएसआर लगभग 1,130 रुपये
- अपने स्वयं की निधि का उपयोग करके 3 पानी की टंकियाँ बनाई और 5 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया
- घर-घर जाकर कचरा संग्रहण की व्यवस्था लागू की, जिससे अप्रबंधित कचरे में 60% की कमी आई
- बिजली की लागत में कटौती करते हुए 50 सौर स्ट्रीटलाइट लगाई
- परिचालन व्यय में 80% आत्मनिर्भरता हासिल की



सर्वोत्तम पद्धतियों/ उपलब्धियों पर विडियो: <https://youtu.be/KfvNvHIFeYQ?si=wPz1pLKT-iGeTHhH>



Panchayat Kshamta Nirmaan Sarvottam Sansthan Puraskar (PKNSSP)- 2025



सशक्त पंचायत सतत विकास

Panchayat Kshamta Nirmaan Sarvottam Sansthan Puraskar is for those Institutions which have provided institutional support to GPs in achieving Localization of Sustainable Development Goals (LSDGs). Institutions at State/Union Territory level provides technical and knowledge-based assistance to Panchayati Raj Institutions through capacity-building of their elected representatives and functionaries for implementing development programs and service delivery along with conducting research & innovations on key related areas to strengthen rural governance at grassroots levels.

Goals and Targets

- 🌱 Capacity Building: Enhance the governance, planning, and financial management skills of Panchayats through structured training programs
- 🌱 Localization of Sustainable Development Goals (LSDGs): Enable Panchayats to translate global SDGs into actionable local development plans (Panchayat Development Plans)
- 🌱 Realizing SDGs: Prepare and align training modules and activities of Panchayats with LSDGs
- 🌱 Data-driven Planning and Research: Evidence-based research and decision-making to monitor progress on SDGs by Panchayats

Role of Institutions

- 🌱 Training and Capacity Building of Panchayats: Conduct training sessions for Panchayat members, Training of Trainers with participatory training methodologies on topics such as resource mobilization, participatory planning, project implementation, digital governance etc.
- 🌱 Policy Advocacy: Provide necessary support to Panchayats on policy frameworks for achieving SDGs
- 🌱 Monitoring and Evaluation: Develop tools and mechanisms to monitor the progress of Panchayat initiatives aligned with SDGs
- 🌱 Knowledge Sharing: Act as a repository of best practices and case studies, helping Panchayats to adopt innovative solutions for local development
- 🌱 Technical Support: Offer expertise in areas like finance, technology, and community engagement to address complex rural challenges
- 🌱 Collaboration and Networking: Facilitate partnerships with NGOs, academic institutions, and international organizations to bring additional resources and expertise to Panchayats

पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार (पीकेएनएसएसपी)- 2025



सशक्त पंचायत सतत विकास

पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार उन संस्थाओं के लिए है जिन्होंने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) को प्राप्त करने में ग्राम पंचायतों को संस्थागत सहायता प्रदान की है। राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर संस्थाएँ अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के माध्यम से विकास कार्यक्रमों और सेवा प्रदायगी को लागू करने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए प्रमुख संबंधित क्षेत्रों पर अनुसंधान और नवाचारों का संचालन करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को तकनीकी और ज्ञान-आधारित सहायता प्रदान करती हैं।

लक्ष्य और उद्देश्य

- क्षमता निर्माण: संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पंचायतों के शासन, नियोजन और वित्तीय प्रबंधन कौशल को बढ़ाना
- सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (एलएसडीजी): पंचायतों को वैश्विक एसडीजी को कार्रवाई योग्य स्थानीय विकास योजनाओं (पंचायत विकास योजनाओं) में बदलने में सक्षम बनाना
- एसडीजी को साकार करना: पंचायतों के प्रशिक्षण मॉड्यूल और गतिविधियों को एलएसडीजी के साथ तैयार करना और संरेखित करना
- डेटा-संचालित योजना और अनुसंधान: पंचायतों द्वारा एसडीजी पर प्रगति की निगरानी के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और निर्णय

संस्थाओं की भूमिका

- पंचायतों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: पंचायत सदस्यों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना, संसाधन जुटाना, सहभागी योजना, परियोजना कार्यान्वयन, डिजिटल शासन आदि जैसे विषयों पर सहभागी प्रशिक्षण पद्धतियों के साथ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना
- नीतियों की वकालत: सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीतिगत ढांचे पर पंचायतों को आवश्यक सहायता प्रदान करना
- निगरानी और मूल्यांकन: सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप पंचायत पहलों की प्रगति की निगरानी के लिए उपकरण और प्रणाली को विकसित करना
- ज्ञान साझा करना: सर्वोत्तम प्रथाओं और केस अध्ययनों के भंडार के रूप में कार्य करना, पंचायतों को स्थानीय विकास के लिए नवीन समाधान अपनाने में सहायता करना
- तकनीकी सहायता: जटिल ग्रामीण चुनौतियों का समाधान करने के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक सहभागिता जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करना
- सहयोग और नेटवर्किंग: पंचायतों तक अतिरिक्त संसाधन और विशेषज्ञता पहुंचाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी को सुगम बनाना

Best Practices of awardee Gram Panchayats: Panchayat Kshamta Nirmaan Sarvottam Sansthan Puraskar (PKNSSP)- 2025

Rank 1: Kerala Institute of Local Administration (KILA), Kerala

Profile of the Institution

KILA, established in 1990, is a nodal capacity development institute in Kerala, recognized as a research center by the Central University of Kerala in 2014. It operates with 15 faculty members, 3,000 trainers, and six regional centers, focusing on local governance, decentralization, and capacity building through research, training, and publications.



Key Achievements

- 🌸 6450 trainings conducted during year 2023-24 for Elected Representatives (ERs) and functionaries
- 🌸 Around 21 thousand ERs and 2.4 lakh line deptt. functionaries trained in year 2023-24
- 🌸 Has a Project Management Unit
- 🌸 Achieved ISO certification for all Gram and Block Panchayats in Kerala.
- 🌸 Enabled 260+ local governments to prepare Local Action Plans for Climate Change (LAPCC)
- 🌸 Developed the DCAT tool (Disaster and Climate Action Tracker) for planning and monitoring
- 🌸 Built and mainstreamed a custom SDG Dashboard and Local Indicator Framework for local governance
- 🌸 Led extreme poverty identification using tailored tools and training
- 🌸 Operates multiple regional and thematic centres (e.g., gender, SDGs, tribal dev., urban governance)
- 🌸 Supports ecosystem-based disaster risk reduction, skill training, and water-soil testing
- 🌸 Launched CANALPY project in Alappuzha to restore canals in partnership with IIT Bombay
- 🌸 Won the Chief Minister's Award for its in-house online training and monitoring system
- 🌸 Runs PG programs through the Institute of Public Policy & Leadership (IPPL)



Video on best practices/achievements: <https://youtu.be/N2H1FGsGo2s?si=kYn-xKiCLx8Tongn>



Rank 2: State Institute for Rural Development and Panchayati Raj (SIRD&PR), Odisha

Profile of the Institution

SIRD & PR, Odisha conducts training through various formats, including in-house, off-campus, and cascading modes at district and block levels, supported by 19 District Panchayat Resource Centres, 3 Extension Training Centres, and 314 Panchayat Samitis. This initiative enhances knowledge dissemination and has refined the State Panchayat Award criteria by incorporating NPA standards, Central Finance Commission and State Finance Commission grant utilization, and OSR metrics for more impactful recognition.



Key Achievements

- 🌸 2795 trainings conducted during year 2023-24 for Elected Representatives (ERs) and functionaries
- 🌸 Around 51 thousand ERs and 1.09 lakh line deptt. functionaries trained in year 2023-24
- 🌸 Has a Project Management Unit
- 🌸 Introduced 15-day induction modules for newly appointed JEs, GPDOs, and PEOs (252 trained)
- 🌸 Developed and implemented Mahila Sabha and Bal Sabha guidelines.
- 🌸 Launched "Local Champion" and "Beginner to Achiever" for performance tracking and mentorship
- 🌸 Deployed a digital portal (tmpr.sird.odisha.gov.in) for real-time training and participant monitoring
- 🌸 Mentored 4,562 Sarpanches and 1,250 PEOs through the Ownership initiative
- 🌸 Drafted key governance tools: OSR Rules, PESA Rules, Citizens Charter, and 9 thematic modules
- 🌸 Enhanced award assessment criteria by incorporating financial sustainability metrics



Video on best practices/achievements: <https://youtu.be/5b94Piz9KTA?si=0LDYSkXRGzULvdzE>



Rank 3: State Institute of Panchayat and Rural Development (SIP&RD), Assam

Profile of the Institution

(SIP&RD), Assam was established in September 1987 and became an autonomous body in 1998 under the Societies Registration Act, 1860. In response to a directive from the Ministry of Panchayati Raj, it was redesignated as the State Institute of Panchayat & Rural Development (SIPRD) on 11th July 2016. The institute's vision is to be a center of excellence in training and research for rural development and Panchayati Raj, and its mission is to build the capacity of stakeholders for better governance and implementation of development programs. SIPRD operates from 2 campuses in Guwahati, with 12 Extension Training Centres and 11 functional District Panchayat Resource Centres (12 more underway), supported by 87 faculty members and a network of trained master trainers.



Key Achievements

- 🌸 5975 trainings conducted during year 2023-24 for Elected Representatives (ERs) and functionaries
- 🌸 Around 14 thousand ERs and 25-thousand-line deptt. functionaries trained in year 2023-24
- 🌸 Has a Project Management Unit
- 🌸 Anchored People's Plan Campaign across the state (GPDP, BPDP, DPDP preparation).
- 🌸 Delivered SDG-focused training in 9 thematic areas (e.g., gender, livelihood, drinking water)
- 🌸 Created 6 PMAY-G model houses as live demonstration tools for practical training
- 🌸 Implemented an MIS system (siprdassam.org) for training monitoring and reporting
- 🌸 Established 12 Extension Training Centres and 11+ District Panchayat Resource Centres
- 🌸 Built a trained network of Master Trainers/Resource Persons through Training of Trainers
- 🌸 Coordinated and mentored Panchayats for Panchayat Development Index (PDI) rollout



Video on best practices/achievements: <https://youtu.be/64Lu9j2Xx7k?si=PjXTncmqbH2N9yFp>



पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों की सर्वोत्तम पद्धतियाँ: पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार - 2025

रैंक 1: केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (किला), केरल

संस्था का परिचय

1990 में स्थापित केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान, केरल में एक नोडल क्षमता विकास संस्थान है, जिसे 2014 में केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। यह 15 संकाय सदस्यों, 3,000 प्रशिक्षकों और छह क्षेत्रीय केंद्रों के साथ काम करता है, जो अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रकाशनों के माध्यम से स्थानीय शासन, विकेंद्रीकरण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।



प्रमुख उपलब्धियाँ

- वर्ष 2023-24 के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई.आर.) और पदाधिकारियों के लिए 6450 प्रशिक्षण आयोजित किए गए
- वर्ष 2023-24 में लगभग 21 हजार ई.आर. और 2.4 लाख लाइन विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- संस्था की एक परियोजना प्रबंधन इकाई है
- केरल में सभी ग्राम और ब्लॉक पंचायतों के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त किया गया।
- 260 से अधिक स्थानीय सरकारों को जलवायु परिवर्तन के लिए स्थानीय कार्य योजना (LAPCC) तैयार करने में सक्षम बनाया गया
- योजना और निगरानी के लिए डीसीएटी उपकरण (आपदा और जलवायु कार्रवाई ट्रैकर) विकसित किया गया
- स्थानीय शासन के लिए एक कस्टम एसडीजी डैशबोर्ड और स्थानीय संकेतक फ्रेमवर्क का निर्माण और उसे मुख्यधारा में लाना
- अनुकूलित उपकरणों और प्रशिक्षण का उपयोग करके चरम गरीबी की पहचान करना
- अनेक क्षेत्रीय एवं विषयगत केन्द्रों का संचालन करता है (जैसे, लिंग, सतत विकास लक्ष्य, जनजातीय विकास, शहरी शासन)
- पारिस्थितिकी तंत्र आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण, कौशल प्रशिक्षण और जल-मृदा परीक्षण में सहयोग करता है
- आईआईटी बॉम्बे के साथ साझेदारी में नहरों को बहाल करने के लिए अलप्पुझा में कैनालपी परियोजना शुरू की गई
- अपनी आंतरिक ऑनलाइन प्रशिक्षण और निगरानी प्रणाली के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार प्राप्त किया है
- सार्वजनिक नीति एवं नेतृत्व संस्थान (आईपीपीएल) के माध्यम से पीजी कार्यक्रम चलाता है



सर्वोत्तम पद्धतियों/उपलब्धियों पर वीडियो: <https://youtu.be/N2H1FGsGo2s?si=kYn-xKiCLx8Tongn>



रैंक 2: राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडी एंड पीआर), ओडिशा

संस्था का परिचय

एसआईआरडी एंड पीआर, ओडिशा जिला और ब्लॉक स्तर पर इन-हाउस, ऑफ-कैंपस और कैस्केडिंग मोड सहित विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित करता है, जिसे 19 जिला पंचायत संसाधन केंद्रों, 3 विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों और 314 पंचायत समितियों द्वारा सहायता दी जाती है। यह पहल ज्ञान प्रसार को बढ़ाती है और अधिक प्रभावशाली मान्यता के लिए एनपीए मानकों, केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग अनुदान उपयोग और ओएसआर मेट्रिक्स को शामिल करके राज्य पंचायत पुरस्कार मानदंडों को परिष्कृत करती है।



प्रमुख उपलब्धियाँ

- वर्ष 2023-24 के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई.आर.) और पदाधिकारियों के लिए 2795 प्रशिक्षण आयोजित किए गए
- वर्ष 2023-24 में लगभग 51 हजार ई.आर. तथा 1.09 लाख लाइन विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- एक परियोजना प्रबंधन इकाई है
- नव नियुक्त जेई, जीपीडीओ और पीईओ (252 प्रशिक्षित) के लिए 15 दिवसीय प्रेरण मॉड्यूल शुरू किया गया।
- महिला सभा और बाल सभा के दिशानिर्देश विकसित और कार्यान्वित किए गए।
- प्रदर्शन ट्रेकिंग और मेंटरशिप के लिए “लोकल चैंपियन” और “बीगिनर टू अचीवर” लॉन्च किया गया
- वास्तविक समय प्रशिक्षण और प्रतिभागियों की निगरानी के लिए एक डिजिटल पोर्टल (tmpsird.odisha.gov.in) स्थापित किया गया
- स्वामित्व पहल के माध्यम से 4,562 सरपंचों और 1,250 पी.ई.ओ. को मार्गदर्शन दिया गया
- प्रमुख शासन उपकरण तैयार किए गए: OSR नियम, पेसा (PESA) नियम, नागरिक चार्टर, और 9 विषयगत मॉड्यूल
- वित्तीय स्थिरता मीट्रिक्स को शामिल करके पुरस्कार मूल्यांकन मानदंड को बढ़ाया गया



सर्वोत्तम पद्धतियों/उपलब्धियों पर वीडियो: <https://youtu.be/5b94Piz9KTA?si=0IDYSkXRGzULvdzE>



बैक 3: राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईपी एंड आरडी), असम

संस्था का परिचय

(एसआईपी एंड आरडी), असम की स्थापना सितंबर 1987 में हुई थी और 1998 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त निकाय बन गया। पंचायती राज मंत्रालय के निर्देश के उत्तर में, इसे 11 जुलाई 2016 को राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईपीआरडी) के रूप में फिर से नामित किया गया। संस्थान का विजन ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता का केंद्र बनना है, और इसका मिशन बेहतर शासन और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना है। एसआईपीआरडी गुवाहाटी में 2 परिसरों से संचालित होता है, जिसमें 12 विस्तार प्रशिक्षण केंद्र और 11 कार्यात्मक जिला पंचायत संसाधन केंद्र (12 और निर्माणाधीन) हैं, जिन्हें 87 संकाय सदस्यों और प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षकों के नेटवर्क द्वारा सहयोग किया जाता है।



प्रमुख उपलब्धियां

- 🌸 वर्ष 2023-24 के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई.आर.) और पदाधिकारियों के लिए 5975 प्रशिक्षण आयोजित किए गए
- 🌸 वर्ष 2023-24 में लगभग 14 हजार ई.आर. तथा 25 हजार लाइन विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया
- 🌸 एक परियोजना प्रबंधन इकाई है
- 🌸 पूरे राज्य में जन योजना अभियान (जीपीडीपी, बीपीडीपी, डीपीडीपी तैयारी) चलाया गया
- 🌸 9 विषयगत क्षेत्रों (जैसे, लिंग, आजीविका, पेयजल) में एसडीजी-केंद्रित प्रशिक्षण दिया गया
- 🌸 व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए लाइव प्रदर्शन उपकरण के रूप में 6 पीएमएवाई-जी मॉडल घर बनाए गए
- 🌸 प्रशिक्षण निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए MIS प्रणाली (siprdassam.org) लागू की गई
- 🌸 12 विस्तार प्रशिक्षण केंद्र और 11+ जिला पंचायत संसाधन केंद्र स्थापित किए गए
- 🌸 ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के माध्यम से मास्टर प्रशिक्षकों/संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षित नेटवर्क बनाया गया
- 🌸 पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) के क्रियान्वयन के लिए पंचायतों का समन्वयन एवं मार्गदर्शन किया गया



सर्वोत्तम पद्धतियों/उपलब्धियों पर वीडियो: <https://youtu.be/64Lu9j2Xx7k?si=PjXTncmqbH2N9yFp>





पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Panchayati Raj
Government of India



सशक्त पंचायत सतत विकास



<https://panchayat.gov.in/>

<https://panchayataward.gov.in/>

https://twitter.com/MoPR_Gol

<https://www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj>

<https://www.instagram.com/MinistryOfPanchayatiRaj>

<https://www.youtube.com/@MinistryOfPanchayatiRaj>